Azadi Ka Amrit Mahotsav

GURU DEEKSHAA IAS

सम्पूर्ण-संक्षिप्त-समर्थ

CURRENT AFFAIRS गुरु

UPSC/State PSC परीक्षा की तैयारी करने वाले हिंदी माध्यम के छात्रो के लिए

20TH AUGUST 2022

FOR DAILY FREE CURRENT AFFAIRS
Follow Our Youtube Channel

Guru Deekshaa Hindi

INDEX

DAILY CURRENT AFFAIRS NOTES

20th August 2022

1. - यूएनसीएलओएस के बारे में: 3
   (i) के बारे में: 3
   (ii) कन्वेंशन ने तीन नए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण किया है: 3
   (iii) सुरक्षा को आगे बढ़ाने और समुद्री हितों की रक्षा के लिए हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत के प्रयास: 3

2. - मौद्रिक नीति समिति का विवरण: 4
   (i) के बारे में: 4
   (ii) कार्य: 4
   (iii) एमपीसी की संरचना: 4
   (iv) सदस्यों और शर्तों का चयन: 4
   (v) निर्णय कैसे किए जाते हैं? 4
   (vi) क्या है आरबीआई की मौद्रिक नीति? 4
   (vii) मौद्रिक नीति किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है? 5
   (viii) मौद्रिक नीति के उपकरण कैसे प्रबंधित किए जाते हैं? 5

3. - भारत रत्न के बारे में: 6
   (i) के बारे में: 6
   (ii) अन्य महत्वपूर्ण जानकारी: 6
   (iii) निष्कर्ष: 6

4. - मुक्त व्यापार समझौतों का विवरण: 7
   (i) के बारे में: 7
   (ii) भारत और एफटीए: 7
   (iii) अन्य सूचना: 7
   (iv) एशिया-प्रशांत व्यापार समझौता (APTA) 7

(v) भारत की विदेश व्यापार नीति के मुद्दे:..... 7

संपादकीय विश्लेषण..... 9

1. भारत में एड्स नियंत्रण:..... 9
   (i) पार्श्वभूमि:..... 9
   (ii) भारत की एड्स स्थिति:..... 9
   (iii) सरकार की पहल:..... 10
   (iv) वैश्विक एड्स प्रतिक्रिया में भारत की भागीदारी:..... 10
   (v) एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी जानकारी:..... 10
   (vi) कैसे आगे बढ़ा जाए:..... 11

2. भारत बांग्लादेश संबंध:..... 12
   (i) भारत-बांग्लादेश संबंध:..... 12
   (ii) वित्तीय संबंध:..... 12
   (iii) कनेक्टिविटी:..... 12
   (iv) नदियों के संदर्भ में सहयोग:..... 12
   (v) रक्षा में सहयोग:..... 12
   (vi) चिकित्सा उद्योग संबंध:..... 12
   (vii) बहुपक्षीय मंचों में सहयोग:..... 12
   (viii) नई तरक्की:..... 13
   (ix) चुनौतियां:..... 13
   (x) अन्य मामले:..... 13
   (xi) आगे बढ़ना:..... 14

1. - यूएनसीएलओएस के बारे में:

जीएस II

विषय→अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

के बारे में:

- 1982 में दत्तक ग्रहण और हस्ताक्षर हुआ।
- यह वर्ष 1994 में प्रभावी हो गया।
- अप्रैल 1958 के चार जिनेवा सम्मेलनों में उच्च समुद्र, महाद्वीपीय शेल्फ, मत्स्य पालन और उच्च समुद्रों पर जीवित संसाधनों के संरक्षण को संबोधित किया गया था।
- अब, सभी समुद्री और समुद्री संबंधी गतिविधियां कन्वेंशन द्वारा शासित हैं।
- आंतरिक जल, प्रादेशिक सागर, सन्निहित क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड), और उच्च समुद्र इसके पांच मुख्य क्षेत्र हैं। समुद्र का कानून इस नियमन का दूसरा नाम है।
- UNCLOS एकमात्र अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो समुद्री क्षेत्र पर राज्य की संप्रभुता के लिए आधार तैयार करता है। यह विशिष्ट समुद्री क्षेत्रों पर विभिन्न कानूनी स्थिति प्रदान करता है।

कन्वेंशन ने तीन नए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण किया है:

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण
- महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाओं पर आयोग

सुरक्षा को आगे बढ़ाने और समुद्री हितों की रक्षा के लिए हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत के प्रयास:

- भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के आधार पर खुले नेविगेशन और ओवरफ्लाइट के साथ-साथ अप्रतिबंधित व्यापार को बढ़ावा दिया, विशेष रूप से यूएनसीएलओएस 1982 द्वारा प्रदर्शित किया गया।
- UNCLOS के लिए एक स्टेट पार्टी के रूप में, भारत ने UNCLOS के लिए सर्वोच्च सम्मान का समर्थन किया, जिसने समुद्र और महासागरों को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे की स्थापना की।
- सभी के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने अपने पड़ोसियों (सागर) के साथ अपने समुद्री सहयोग को बढ़ाया।
- समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और किसी भी आकस्मिकता के लिए तैयार होने के लिए नौसैनिक जहाजों और विमानों की "मिशन आधारित तैनाती" सहित उपाय किए गए हैं।
- *स्रोत→ हिन्दू*

2. - मौद्रिक नीति समिति का विवरण:

जीएस III

विषय→भारतीय अर्थव्यवस्था

के बारे में:

- सरकार द्वारा नियुक्त मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), जो आरबीआई के प्रभारी हैं, को रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर और नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) जैसे उपकरणों का उपयोग करके मौद्रिक नीति बनाने का काम सौंपा गया है।
- यह भारत की केंद्र सरकार द्वारा 1934 में संशोधित RBI अधिनियम की धारा 45ZB के अनुपालन में बनाया गया था।

कार्य:

- एमपीसी एमएसएफ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट सुविधा सहित विभिन्न नीतिगत दरों के चयन के लिए जिम्मेदार है।

एमपीसी की संरचना:

- कमेटी में छह लोग शामिल होंगे। सरकार छह में से तीन उम्मीदवार उतारेगी। एमपीसी को सौंपा गया कोई भी सरकारी प्रतिनिधि नहीं होगा।
- अन्य तीन सदस्य आरबीआई से होंगे, और गवर्नर पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय बैंक के कार्यकारी निदेशक और मौद्रिक नीति के प्रभारी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर दोनों सदस्य होंगे।

सदस्यों और शर्तों का चयन:

- चयन: कैबिनेट सचिव, आरबीआई गवर्नर, आर्थिक मामलों के सचिव, और अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्त और मौद्रिक नीति के तीन विशेषज्ञ खोज-सह-चयन समिति बनाएंगे जो एमपीसी के लिए सरकार के उम्मीदवारों का निर्धारण करेगी। .
- एमपीसी सदस्यों को चार साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं।

निर्णय कैसे किए जाते हैं?

- बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं, प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। बराबरी की स्थिति में राज्यपाल का निर्णायक मत होगा; हालाँकि, उसके पास अन्य पैनलिस्टों द्वारा लिए गए निर्णयों को रद्द करने की शक्ति नहीं होगी।

क्या है आरबीआई की मौद्रिक नीति?

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की "मौद्रिक नीति" से तात्पर्य है कि यह कैसे मौद्रिक संसाधनों का उपयोग करता है जो जीडीपी बढ़ाने और मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अपने नियंत्रण में हैं।
- 1934 का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आरबीआई को मौद्रिक नीति पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है।

मौद्रिक नीति किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है?

- चक्रवर्ती समिति की सिफारिशों के अनुसार, भारत की मौद्रिक नीति को नए वित्तीय संस्थानों के निर्माण के साथ-साथ आर्थिक विकास, इक्विटी और सामाजिक न्याय का समर्थन करना चाहिए।
- जबकि भारत सरकार का लक्ष्य जीडीपी विकास की गति को तेज करना है, फिर भी आरबीआई मुद्रास्फीति को एक सहनीय स्तर पर रखने के लिए काम कर रहा है।
- देश के मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने और इसके मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता के लिए, मौद्रिक नीति समिति इष्टतम नीतिगत ब्याज दर का चयन करती है।

मौद्रिक नीति के उपकरण कैसे प्रबंधित किए जाते हैं?

- मौद्रिक नीति उपकरण दो श्रेणियों में आते हैं: गुणात्मक साधन और मात्रात्मक साधन।
- मात्रात्मक साधनों की सूची में ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, सीमांत स्थायी सुविधा और तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) शामिल हैं।
- गुणात्मक साधनों के उदाहरणों में नैतिक अनुनय, प्रत्यक्ष कार्रवाई और लाभ मार्जिन में परिवर्तन शामिल हैं।

- ***स्रोत→ इंडियन एक्सप्रेस***

3. - भारत रत्न के बारे में:

जीएस II

विषय→संवैधानिक प्रावधान

के बारे में:

- भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 1954 में स्थापित किया गया था।
- यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए प्रशंसा में दिया जाता है, चाहे किसी व्यक्ति की जाति, पेशे, रैंक या यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना।
- प्रधान मंत्री के प्रस्ताव पर, भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष तीन से अधिक भारत रत्न पुरस्कार प्रदान नहीं कर सकते हैं।
- पुरस्कार के विजेता को एक पदक और एक सनद (प्रमाण पत्र) प्राप्त होता है जिस पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। पुरस्कार का कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है।
- विजेताओं को अपने नाम के आगे भारत रत्न लगाने या भारत रत्न से समाप्त करने की अनुमति नहीं है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) में कहा गया है।
- भारत रत्न से सम्मानित होने के लिए भारतीय नागरिक होने की आवश्यकता नहीं है।
- यह प्रतिष्ठित सम्मान मदर टेरेसा को दिया गया था, जिन्हें 1980 में एक प्राकृतिक भारतीय नागरिक एग्नेस गोंक्सा बोजाक्सीयू के नाम से भी जाना जाता है। 1987 में, गैर-भारतीयों नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी इसे अर्जित किया। (1990)।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:

- रिवर्स पर सूर्य की तस्वीर के साथ एक गोलाकार स्वर्ण पदक पहले पुरस्कार (व्यास में 35 मिमी) के रूप में कार्य करता है।
- फूल के ऊपर, देवनागरी लिपि में "भारत रत्न" शब्द एक पुष्पांजलि के भीतर उकेरा गया था।
- प्लेटिनम के पीछे राष्ट्रीय प्रतीक "सत्यमेव जयते" उत्कीर्ण है, जो देवनागरी लिपि में भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है।
- कोलकाता में अलीपुर टकसाल भारत रत्न पदक के साथ-साथ पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री और परम वीर चक्र सहित अन्य सम्मानित सम्मानों का निर्माण करता है।

निष्कर्ष:

- भारत रत्न नस्ल, पेशे, रैंक या लिंग की परवाह किए बिना "अनुकरणीय सेवा / उच्चतम डिग्री के प्रदर्शन की सराहना में" से सम्मानित किया जाता है। 1954 के नियमों के अनुसार, पदक केवल कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा की श्रेणियों में दिया जा सकता था। "मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र" को शामिल करने के लिए दिसंबर 2011 में दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया था। मरणोपरांत सम्मान पर रोक लगाने वाले 1954 के क़ानून को जनवरी 1955 के अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री 1966 में मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे।

- *स्रोत→ हिन्दू*

4. - मुक्त व्यापार समझौतों का विवरण:

प्रीलिम्स विशिष्ट विषय

के बारे में:

- यह दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात नियमों को ढीला करने का एक समझौता है।
- एक मुक्त व्यापार नीति के तहत अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार माल और सेवाओं के आदान-प्रदान में बाधा डालने वाले सरकारी कर, कोटा, सब्सिडी और प्रतिबंध कम से कम मौजूद नहीं हैं।
- आर्थिक या व्यापार संरक्षणवाद मुक्त व्यापार की अवधारणा के विरोधी हैं।

भारत और एफटीए:

- भारत द्वारा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से बाहर निकलने का निर्णय लेने के बाद, एक 15-सदस्यीय FTA संगठन जिसमें चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं, FTA वार्ता को भारत के लिए रोक दिया गया था।
- भारत और यूरोपीय संघ के बीच वार्ता की बहाली, जिसे 2013 में निलंबित कर दिया गया था, हालांकि मई 2021 में घोषित किया गया था।
- दोनों पक्ष वर्तमान में इन बहुआयामी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आंतरिक योजना में लगे हुए हैं।
- भारत यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते कर रहा है।
- ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए "अच्छी तरह से आगे बढ़ा" था, जबकि यह यूएई के साथ "अंतिम रूप देने के करीब" था।

अन्य सूचना:

- भारत और मॉरीशस (सीईसीपीए) के बीच एक व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता मौजूद है।
- अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 1995 में दक्षिण एशिया तरजीही व्यापार समझौता (SAPTA) बनाया गया था।
- SAFTA, एक विवश मुक्त व्यापार समझौता, केवल सामान को कवर करता है और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं सहित सभी सेवाओं को बाहर करता है। एक समझौते के अनुसार, जिस पर बातचीत हुई थी, 2016 तक, किसी भी व्यापारिक सामान पर कोई सीमा शुल्क लागत नहीं होगी।

एशिया-प्रशांत व्यापार समझौता (APTA)

- एक तरजीही टैरिफ योजना, जिसे पहले बैंकॉक समझौते के रूप में जाना जाता था, सदस्य देशों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत रियायतों के आदान-प्रदान द्वारा अंतर-क्षेत्रीय वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी।

भारत की विदेश व्यापार नीति के मुद्दे:

- खराब विनिर्माण क्षेत्र: हाल के वर्षों में, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण का योगदान 14% है।

- जर्मनी, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे परिष्कृत और विकसित देशों के लिए तुलनात्मक प्रतिशत क्रमशः 19%, 11%, 25% और 21% है।
- जबकि कम आय वाले देशों के लिए अनुपात 8% है, चीन, तुर्की, इंडोनेशिया, रूस और ब्राजील जैसे उभरते और विकासशील देशों के समान आंकड़े क्रमशः 27%, 19%, 20%, 13% और 9% हैं।
- प्रतिकूल एफटीए: भारत ने पिछले दस वर्षों (आसियान) में मलेशिया, कोरिया गणराज्य, जापान और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं।
- ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये समझौते भारत के आर्थिक साझेदारों के लिए भारत के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद रहे हैं।
- यह विचार कि भारत एक अधिक बंद, संरक्षणवादी बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो रहा है, आत्मानबीर भारत अभियान के कारण खराब हो गया है।

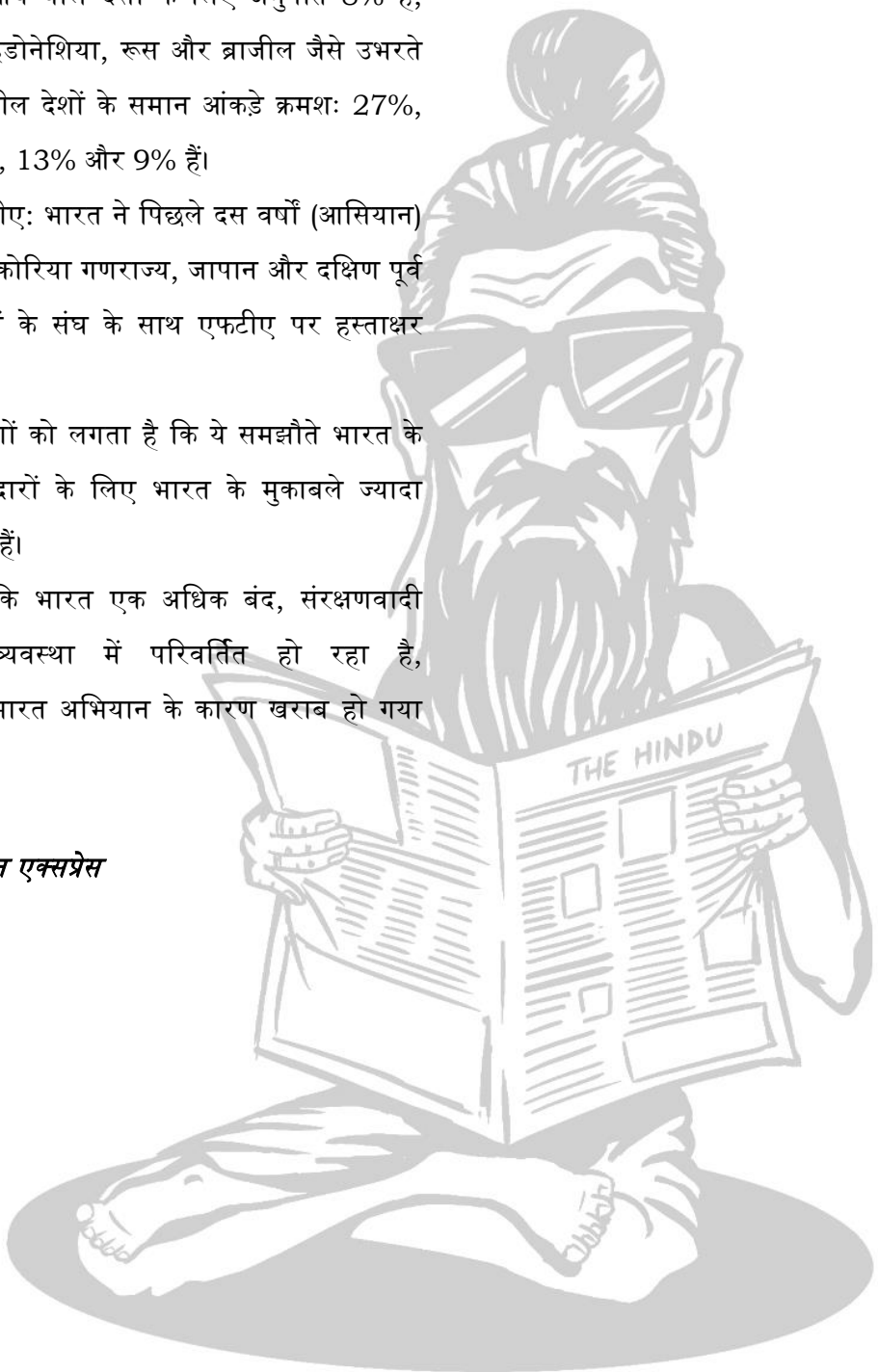

- ***स्रोत→ इंडियन एक्सप्रेस***

संपादकीय विश्लेषण

1. भारत में एड्स नियंत्रण:

पार्श्वभूमि:

- सरकार की सबसे हालिया एचआईवी अनुमान रिपोर्ट (2019) में भविष्यवाणी की गई है कि उस वर्ष भारत में लगभग 23.49 लाख एचआईवी / एड्स रोगी रहेंगे। अनुमान बताते हैं कि 2010 और 2019 के बीच, पूरे देश में नए एचआईवी संक्रमणों की वार्षिक संख्या में 37% की गिरावट आई है।
- यूएनएड्स यह गारंटी देना चाहता है कि 90-90-90 लक्ष्यों को प्राप्त करके 30 मिलियन लोगों की इलाज तक पहुंच हो, जो एचआईवी वाले 90% लोगों को अपनी स्थिति के बारे में जागरूक करने के लिए कहते हैं, उनमें से 90% लोग जो अपनी एचआईवी सकारात्मकता के बारे में जानते हैं उपचार प्राप्त कर रहे हैं, और उपचार प्राप्त करने वालों में से 90% ने वायरल लोड को दबा दिया है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से नाको द्वारा संचालित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) एड्स की रोकथाम, उपचार और जागरूकता निर्माण के लिए नोडल कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है। भारत यूएनएड्स द्वारा निर्धारित 90-90-90 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- इसके अतिरिक्त, भारत ने कहा है कि वह सभी जरूरतमंद रोगियों को मुफ्त माध्यमिक उपचार प्रदान करेगा।
- भले ही केवल 0.27% राष्ट्रव्यापी प्रसार की सूचना दी गई है, फिर भी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताएं मौजूद हैं।

भारत की एड्स स्थिति:

- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रभाग, 35 एचआईवी/एड्स रोकथाम और नियंत्रण समितियों के माध्यम से भारत के एचआईवी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की देखरेख करता है।
- नाको के बड़े हिस्से के लिए धन्यवाद, और दुनिया के औसत से कहीं अधिक तेजी से, देश में एचआईवी / एड्स का प्रसार बहुत कम हो गया है।
- 1995 में महामारी की ऊंचाई के बाद से, यह अनुमान लगाया गया है कि 80% से भी कम नए संक्रमण हुए हैं।
- अनुमानित एड्स से संबंधित मौतों में 2005 में अपने चरम से 71% की गिरावट आई है।
- यूएनएड्स 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, नए संक्रमणों और एड्स से संबंधित मृत्यु दर में औसत वैश्विक गिरावट क्रमशः 47% और 51% थी।
- UNAIDS 1996 में अपनी स्थापना के बाद से एचआईवी को खत्म करने के लिए वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर नेतृत्व, नवाचार और टीम वर्क को निर्देशित और प्रेरित कर रहा है। कॉर्पोरेट मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।

सरकार की पहल:

- 1986 में देश के पहले मामले की पहचान के बाद, भारत सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) की स्थापना की, जो वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एड्स विभाग है।
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) की स्थापना 1992 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एक खंड के रूप में की गई थी। यह 35 रोकथाम और नियंत्रण समितियों के माध्यम से भारत में एचआईवी / एड्स नियंत्रण पहल का प्रबंधन करता है। एचआईवी/एड्स से लड़ने के लिए कानून बनाने और कार्यक्रम चलाने के लिए भारत में मुख्य संगठन नाको कहलाता है।
- भारत में स्थानीय, राज्य और संघीय स्तरों पर एचआईवी / एड्स के मुद्दों पर काम करने वाले कई गैर-सरकारी और समुदाय आधारित संगठन (एनजीओ और सीबीओ) हैं।
- भारत को कई संयुक्त राष्ट्र भागीदारों और द्विपक्षीय फंडर्स से तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

वैश्विक एड्स प्रतिक्रिया में भारत की भागीदारी:

- हर साल एड्स के 2 मिलियन नए मामले सामने आते हैं, और दुनिया भर में एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी प्राप्त करने वालों में से लगभग 66% भारत से दवाओं का उपयोग करते हैं।
- एआरटी के लिए वैश्विक बाजार वर्तमान में 48 अरब होने का अनुमान है, और 2025 तक इसके 83 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है।
- उच्च गुणवत्ता वाली, सस्ती दवाएं देने की उनकी क्षमता के परिणामस्वरूप, भारतीय दवा कंपनियां एड्स के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में आवश्यक हैं।

एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी जानकारी:

- एचआईवी-एड्स के रोगियों के लिए एकमात्र उपलब्ध उपचार एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (एआरटी) है, क्योंकि न तो कोई टीका और न ही कोई इलाज विकास में है।
- एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी एचआईवी, एक रेट्रोवायरस-प्रकार के वायरस (एआरटी) के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा का नाम है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मानक एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (एआरटी), एचआईवी वायरस को दबाने और रोग की प्रगति को रोकने के लिए कम से कम तीन एंटीरेट्रोवाइरल दवाओं के संयोजन का उपयोग करती है।
- विशेष रूप से बीमारी के शुरुआती चरणों में एक शक्तिशाली एआरटी आहार के उपयोग से मृत्यु और पीड़ा की दर में काफी कमी आई है।

कैसे आगे बढ़ा जाए:

- नई बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए, क्षेत्रीय और राज्य की योजनाएँ विकसित की जानी चाहिए।
- आशा कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है, और एड्स से संबंधित नई बाल नीति को एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।
- नशीली दवाओं के व्यसनों को सुइयों का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए, कानून प्रवर्तन को नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और चिकित्सा पेशे के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
- कलंक का सामना करने के कारण, यौनकर्मी स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, चिकित्सा सुविधाओं आदि से संपर्क करने में असमर्थ हैं। इसे संबोधित करने के लिए एक मजबूत नीति की आवश्यकता है।
- नए संक्रमणों में 50% की कमी के अलावा, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) के चरण IV का उद्देश्य सभी एचआईवी/एड्स रोगियों को पूर्ण देखभाल, सहायता और चिकित्सा प्रदान करना है।
- एड्स को समाप्त करने पर 2016 की राजनीतिक घोषणा की बदौलत वैश्विक समुदाय 2030 तक बीमारी के उन्मूलन के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है, एक निरंतर, लेजर-केंद्रित प्रयास जो कि बढ़ी हुई शक्ति के साथ किया जाता है, की आवश्यकता है।

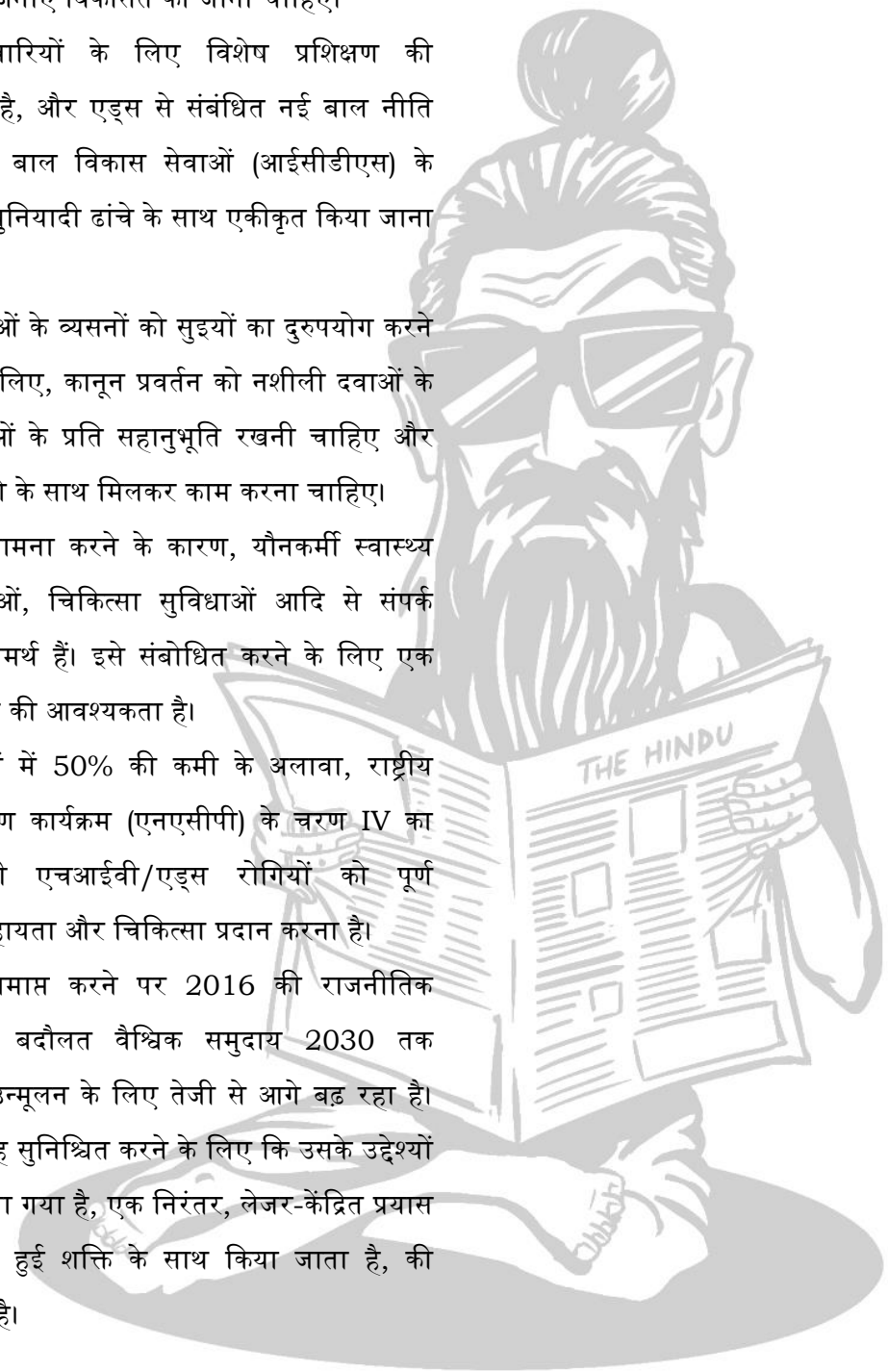

2. भारत बांग्लादेश संबंध:

भारत-बांग्लादेश संबंध:

- भारत दिसंबर 1971 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद बांग्लादेश के साथ राजनयिक संबंधों को मान्यता देने और स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था।

वित्तीय संबंध:

- बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है और बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में, भारत ने 1.26 बिलियन डॉलर लाते हुए बांग्लादेश को 8.2 बिलियन डॉलर का निर्यात किया।

कनेक्टिविटी:

- भारत के चिलाहाटी और हल्दीबाड़ी (बांग्लादेश) को जोड़ने वाली रेलवे लाइन को फिर से खोलने के लिए दोनों देशों ने मिलकर काम किया।
- बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (बीबीआईएन) पहल मोटर वाहन समझौते को तेजी से संचालित करने के लिए, सक्षम करने वाले समझौता ज्ञापन पर तुरंत हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया।
- अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार (PIWTT) पर प्रोटोकॉल के दूसरे जोड़ पर अभी हस्ताक्षर किए गए थे।
- 2015 में कोलकाता से ढाका और अगरतला के लिए बस सेवा का शुभारंभ हुआ। इसके परिणामस्वरूप कोलकाता और अगरतला के बीच 1,650 किलोमीटर की दूरी 500 किलोमीटर कम हो गई।

नदियों के संदर्भ में सहयोग:

- भारत और बांग्लादेश 54 नदियों से जुड़े हुए हैं।
- एक द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) जून 1972 से दोनों देशों के बीच संचार बनाए रखने और साझा नदी प्रणालियों से लाभ को अधिकतम करने के लिए काम कर रहा है।

रक्षा में सहयोग:

- सीमा प्रबंधन: बांग्लादेश और भारत एक भूमि सीमा साझा करते हैं जो 7 किमी लंबी है, जिससे यह पड़ोसी के साथ देश की सबसे लंबी भूमि सीमा बन जाती है।
- अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान-प्रदान के बाद जून 2015 में भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता (एलबीए) लागू हुआ।
- दोनों देशों के सशस्त्र बलों को शामिल करने वाले कई संयुक्त सैन्य अभ्यास, जैसे व्यायाम संप्रति और व्यायाम मिलान।

चिकित्सा उद्योग संबंध:

- बांग्लादेश भारतीय अस्पतालों में अंतरराष्ट्रीय रोगियों का 35% से अधिक बनाता है।
- सिर्फ बांग्लादेश से, भारत को अपने राजस्व का 50% से अधिक चिकित्सा पर्यटन से प्राप्त होता है।

बहुपक्षीय मंचों में सहयोग:

- महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठनों के सदस्य, जैसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) और बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक)।

- COVID-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए सहयोग में मार्च 2020 में सार्क नेताओं के वीडियो सम्मेलन में बांग्लादेश की भागीदारी और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए सार्क आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष का निर्माण शामिल है। यूएनएससी जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एसडीजी हासिल करने में सहयोग।

नई तरक्की:

- भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए और अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए तीन परियोजनाएं शुरू कीं।
- बांग्लादेश के चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग करके भारत से और विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत से माल भेजने की प्रथा।
- बांग्लादेश की फेनी नदी का उपयोग त्रिपुरा पीने के पानी के स्रोत के रूप में करता है।

चुनौतियां:

तीस्ता नदी जल विवाद:

- 2011 के अंतरिम समझौते के अनुसार, भारत और बांग्लादेश दोनों को क्रमशः तीस्ता नदी के पानी का लगभग 42.5 प्रतिशत और 37.5% पानी प्राप्त होगा।
- हालाँकि, पश्चिम बंगाल राज्य ने इस शर्त को खारिज कर दिया है और कभी भी समझौते की पुष्टि नहीं की है, इसलिए इस विषय में संघर्ष अभी भी मौजूद है।

अनिर्दिष्ट अप्रवास एक समस्या है:

- नेशनल रजिस्टर ऑफ नेशनल (एनआरसी), असम में रहने वाले वैध भारतीय नागरिकों की पहचान करने और अनधिकृत बांग्लादेशियों को बेदखल करने के उद्देश्य से एक पहल है, जिसने अतीत में बांग्लादेश में चिंता जताई है।

चीन का प्रभाव:

- बांग्लादेश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का एक सहभागी सदस्य है, हालांकि भारत ने इसमें भाग नहीं लिया है।
- बांग्लादेश चीनी सैन्य हार्डवेयर, विशेष रूप से पनडुब्बियों का एक प्रमुख उपयोगकर्ता है।

अन्य मामले:

- भारत पशु तस्करी, नकली धन हस्तांतरण और सीमावर्ती जिलों में सशस्त्र डकैती से भी चिंतित है।
- अवैध अप्रवासियों की तस्करी, आतंकवाद में उनकी संलिप्तता और भारत में वेश्यावृत्ति सभी भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को जटिल बनाते हैं।
- बांग्लादेश नदियों को जोड़ने और मणिपुर में बराक नदी पर तपाईमुख बांध बनाने के भारत के इरादों का भी विरोध करता है।

आगे बढ़ना:

- भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका नदी के पानी के मुद्दों जैसे तीस्ता के साथ जल्दी से समाधान खोजना है।
- तस्करी, अवैध व्यापार और पशु तस्करी जैसे सीमा मुद्दों से लड़ने के प्रयासों का समन्वय करना।
- सार्क, बिम्सटेक आदि जैसे क्षेत्रीय संगठनों को मजबूत करना और "पड़ोसी पहले" सिद्धांत पर जोर देना
- भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे संबंध उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास, भारत-प्रशांत क्षेत्र की खोज और दक्षिण एशियाई देशों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं।

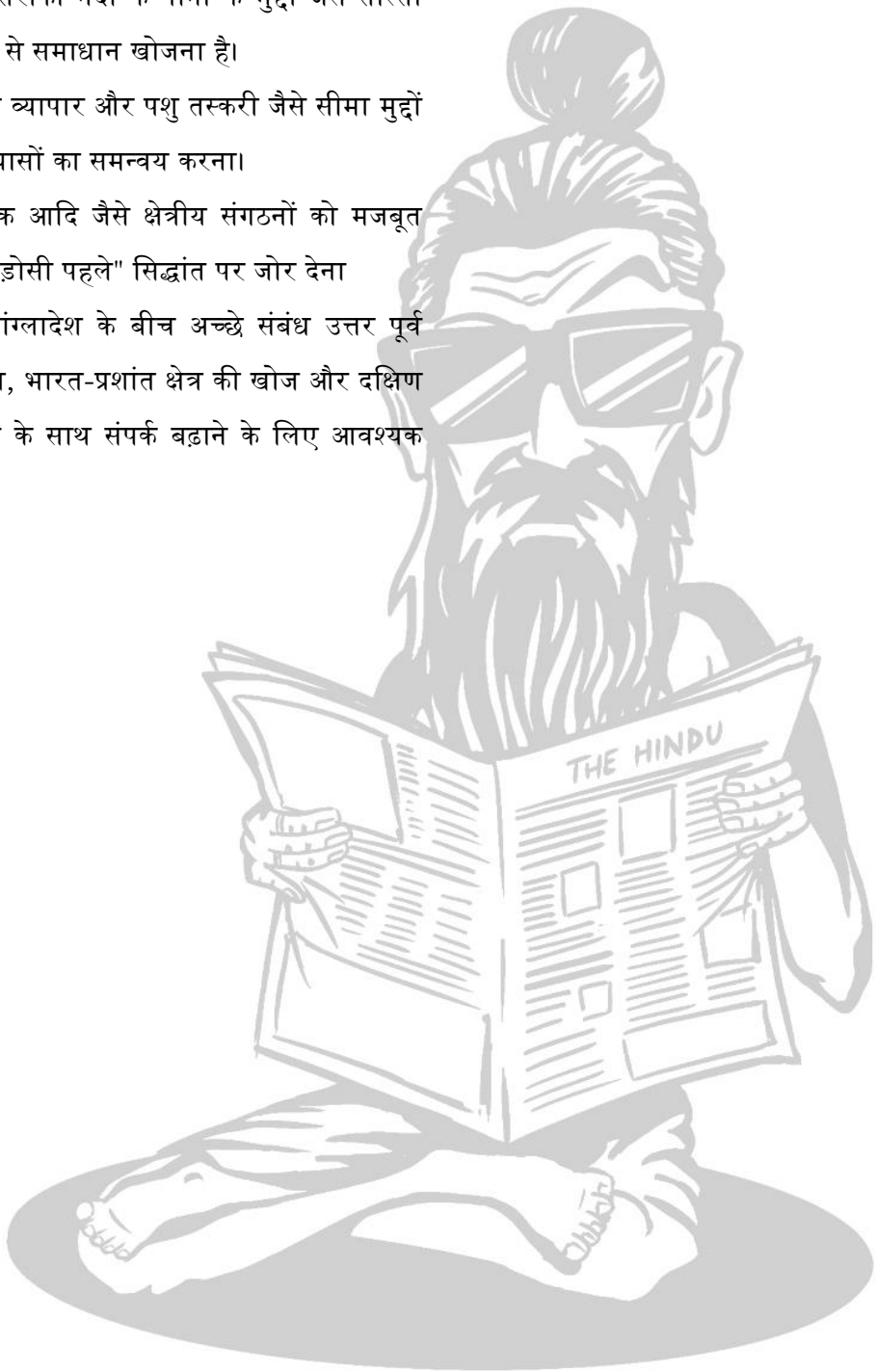

Guru Deekshaa IAS is happy to announce first ever kannada current affairs magazine for kannada medium aspirants of Karnataka. The three important thumb rules for any competitive exam are

Vijay Kumar G

Founder and Director

Guru Deekshaa IAS

- First-NCERT/STATE syllabus books which helps to develop your understanding on the subjects
- Second-Daily current affairs helped to build your further understanding of the events related to your examination, Apart from knowledge it build the personality of an individual which brings in confidence to face any examination.
- Third-Practice previous year question papers and mock test available in the market to train your mind as per the requirement of the examination.

Thousand miles of journey starts with single step, We at Guru Deekshaa have taken this first step towards empowering you to prepare for civil for services. Now its your turn to start preparation and achieve your dream of becoming IAS/IPS.

CALL US FOR MORE DETAILS

76 76 74 98 77

JOIN OFFICIAL TELEGRAM FOR MATERIAL AND UPDATES

@GURU_DEEKSHAAIAS

FOLLOW OUR INSTAGRAM FOR DAILY UPDATES

GURUDEEKSHAA